EXPLANATION

CURRENT AFFAIRS & INDIAN SOCIETY-17 MARCH

1. D

- The "Greater Bay Area" refers to the Chinese government's scheme to link the cities of Hong Kong, Macau, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen and Zhaoqing into an integrated economic and business hub.
- "ग्रेटर बे एरिया" हांगकांग, मकाऊ, ग्वांगझू, शेनझेन, ज़ुहाई, झोंगशान, झोंगशान, Dongguan, हुइझोऊ, जियांगमेन और झाओकिंग शहरों को एकीकृत आर्थिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में जोड़ने के लिए चीनी सरकार की योजना को संदर्भित करता है।

2.A

- Stung by the Rs 11,400 crore fraud in Punjab National Bank, the Reserve Bank of India (RBI) constituted an expert committee under the chairmanship of Y H Malegam, a former member of the Central Board of Directors of RBI, to look into the entire gamut of issues relating to classification of bad loans, rising incidents of frauds and effectiveness of audits.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित पूरी घटना पर गौर करे जिसमे प्रमुखतः खराब ऋणों के वर्गीकरण, धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं और ऑडिट की प्रभावशीलता से संबंधित मुद्दे शामिल है।

3.C

- Italy's Mount Etna volcano has erupted again resulting in more than 130 earthquakes of up to 4.3 in magnitude.
- Mount Etna is the largest active volcano in Europe and one of the world's most frequently erupting volcanoes. It is also the volcano with the longest record of continuous eruption.
- इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी फिर से प्रस्फुटित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 130 से अधिक भूकंप आए हैं, जो 4.3 से अधिक तीव्रता के हैं।
- माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व के सबसे अधिक बार विस्फुटित होने वाले ज्वालामुखियों में से एक है। यह निरंतर विस्फोट के सबसे लंबे रिकॉर्ड वाला ज्वालामुखी भी है।

4.C

- Niti Aayog has released the Second Delta Ranking of the Aspirational Districts Programme. The ranking details the incremental progress achieved by the districts during June to October this year across six key development sectors.
- The districts have been ranked in a transparent basis on parameters across various performance indicators like Health and Nutrition, Education, Skill Development and Basic Infrastructure among others.
- नीति अयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग छह प्रमुख विकास क्षेत्रों में इस साल जून से अक्टूबर के दौरान जिलों द्वारा प्राप्त वृद्धिशील प्रगति का विवरण देती है।
- जिलों को स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों में मापदंडों के आधार पर पारदर्शी आधार पर स्थान दिया गया है।

5.C

- The World Food Programme (WFP) is the food-assistance branch of the United Nations and the world's largest humanitarian organization addressing hunger and promoting food security.
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है एवं विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखमरी को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

6.D

- Olive Ridley turtle is the smallest and most abundant of all sea turtle found in the world.
- It is found in warm waters of the Pacific and Indian oceans.
- It commences its journey from Indian Ocean towards Bay of Bengal during their mating season in October and November every year.

- The Gahirmatha Beach in Kendrapara district of Odisha (India), which is now a part of the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, is the largest breeding ground for these turtles.
- Green turtles and olive ridleys are known to nest in Maharashtra in small numbers. Goa has records of three species of sea turtles: olive ridley, leatherback and green turtles.
- Recently many of these turtles were found dead near the Andhra Pradesh coast.
- ओलिव रिडले कछुआ विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा और सबसे प्रचुर है।
- यह प्रशांत और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाया जाता है।
- यह हर साल अक्टूबर और नवंबर में अपने संभोग के मौसम के दौरान हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है।
- ओडिशा (भारत) के केंद्रपाड़ा जिले में गहिरमाथा तट, जो अब भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है, इन कछुओं के लिए सबसे बड़ा प्रजनन मैदान है।
- हरे रंग के कछुए और ओलिव टर्टल, महाराष्ट्र में कम संख्या में घोंसला बनाने के लिए जानी जाते हैं। गोवा में समुद्री कछुओं की तीन प्रजातियों के रिकॉर्ड हैं: ओलिव रिडले टर्टल, लेदरबैक और हरे कछुए।
- हाल ही में आंध्र प्रदेश तट के पास इनमें से कई कछुए मृत पाए गए थे।

7.A

- The central banks of the UAE and Saudi Arabia have launched a common digital currency called "Aber", which will be used in financial settlements between the two countries through Blockchains and Distributed Ledgers technologies.
- Through this digital currency, both the United Arab Emirates Central Bank (UAECB) and the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) are studying the impact on the improvement and reduction of remittance costs and the assessments of risks.
- यूएई और सऊदी अरब के केंद्रीय बैंकों ने "अबेर" नामक एक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है, जिसका उपयोग ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन-देन में किया जाएगा।
- इस डिजिटल मुद्रा के माध्यम से, संयुक्त अरब अमीरात सेंट्रल बैंक (UAECB) और सऊदी अरब मौद्रिक प्राधिकरण (SAMA) दोनों प्रेषण लागत के सुधार और कटौती और जोखिमों के आकलन पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं।

8.A

- UNESCO has declared 2019 as the International Year of the Period Table of Chemical Elements to commemorate the 150th birthday of the periodic table of chemical elements. The Periodic table of the Chemical elements was first published by Russian scientist Dmitry Mendeleev in the year 1869.
- यूनेस्को ने 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के 150 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रासायनिक तत्वों की अवधि के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडेलीव ने वर्ष 1869 में प्रकाशित किया था।

9.D

- India is going to host the G20 annual summit is 2022 when it celebrates its 75th year of independence and in order exploit it to the full extent, capacity augmentation of available resources and efficient addressal of organizational challenges must be done on time to fill the infrastructure, management and intellectual gap. Indian Prime Minister, Narendra Modi requested Italy to host the 2021 G20 summit instead of 2022 summit which was accepted by Italy.
- भारत G-20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करने जा रहा है, जब यह अपनी आजादी के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहा है और पूरी तरह से इसका फायदा उठाने के लिए, उपलब्ध संसाधनों की क्षमता वृद्धि और संगठनात्मक चुनौतियों का कुशलता से निराकरण, बुनियादी ढाँचा विकसित करना और व्याप्त प्रबंधन एवं बौद्धिक अंतर को समाप्त करने का प्रयास करेगा। भारतीय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने इटली से 2022 शिखर सम्मेलन के बजाय 2021, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का अनुरोध किया जिसे इटली ने स्वीकार कर लिया।

10.C

- The Government has announced a mega pension yojana namely 'Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan' for the unorganised sector workers with monthly income upto Rs. 15,000.
- Only the workers between the age group of 18-40 years can join this scheme.
- The Government will deposit equal matching share in the pension account of the worker every month till the age of 60 years.

- Under the scheme, an assured monthly pension of Rs 3,000 per month will be provided to workers in the unorganised sector after 60 years of age.
- सरकार ने असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए की मासिक आय वाले कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन नामक एक मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है।
- केवल 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के कामगार (कर्मचारी) ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- 60 वर्ष की आयु तक प्रत्येक माह कामगार के पेंशन खाते में सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान (लाभार्थी की आयु के आधार पर) जमा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

11.B

- Statements 1 and 2 are correct: The National Skills Qualifications Framework (NSQF) organizes all qualifications according to a series of levels of knowledge, skills and aptitude. These levels are defined in terms of learning outcomes which the learner must possess regardless of whether they were acquired through formal, non-formal or informal learning. In that sense, the NSQF is a quality assurance framework.
- It is, therefore, a nationally integrated education and competency based skill framework that will provide for multiple pathways, horizontal as well as vertical, both within vocational education and vocational training and among vocational education, vocational training, general education and technical education, thus linking one level of learning to another higher level. This will enable a person to acquire desired competency levels, transit to the job market and, at an opportune time, return for acquiring additional skills to further upgrade their competencies.
- Statement 3 is not correct: The National Skill Development Agency (NSDA) has been mandated to operationalise the NSQF. The NSDA serves as the secretariat for National Skill Qualification Committee (NSQC), the final apex Body where the Qualifications are approved for NSQF alignment.
- कथन 1 और 2 सही हैं: राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) ज्ञान, कौशल और अभिरुचि के अनेक स्तरों के अनुरूप सभी योग्यताएं निर्धारित करता है। इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जो प्रशिक्षार्थी को अवश्य अर्जित करने होते हैं, भले ही ये कौशल उसने औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किए हों। इस संदर्भ में, NSQF एक गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क है।
- अतः यह एक राष्ट्रीय एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित कौशल फ्रेमवर्क है। यह व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के मध्य कई विकल्प (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर) प्रदान करेगा। इस प्रकार यह अधिगम (सीखने) के एक स्तर को अन्य अपेक्षाकृत उच्च स्तर से जोड़ेगा। यह एक व्यक्ति को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने, रोजगार क्षेत्र में उचित समय पर प्रवेश करने तथा अपनी दक्षताओं को अधिक उन्नत बनाने हेतु अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- कथन 3 सही नहीं है: NSQF के संचालन का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) को सौंपा गया है। NSDA राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (NSQC) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि NSQC वह शीर्ष निकाय है जो NSQF संचालन हेतु योग्यताओं को स्वीकृति प्रदान करता है।

12.C

On 22nd November 2018, Government has launched 'Bhasha Sangam', a unique initiative to introduce school students to 22 Indian languages. Bhasha Sangam has been launched under Ek Bharat Shreshtha Bharat. It will continue till the 21 December 2018. Bhasha Sangam is a programme for schools and educational institutions to offer multilingual exposure to students in Indian languages. It also aims to improve linguistic tolerance and respect and promote national integration. There are 22 languages listed in Schedule VIII of Indian Constitution.

22 नवंबर 2018 को, सरकार ने 'भाषा संगम' लॉन्च किया है, जो स्कूल के छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं से अवगत कराने के लिए एक अनूठी पहल है। भाषा संगम "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के तहत शुरू किया गया है। यह 21 दिसंबर 2018 तक जारी रहेगा। भाषा संगम स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक कार्यक्रम है जो छात्रों को भारतीय भाषाओं में बहुभाषी एक्सपोजर प्रदान करता है। इसका लक्ष्य भाषाई सहिष्णुता और सम्मान और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। भारतीय संविधान की अनुसूची VIII में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

13.B

From 21st November to 30th November, Manipur Tourism Department organized an annual cultural festival known as "Sangai Festival" which was previously known as "Tourism Festival". But in 2010 it was renamed after the State Animal of Manipur Sangai Deer. The Sangai Festival is celebrated to promote Manipur as the World Class tourism

destination. The Festival showcases the culture, handloom, handicraft and fine arts, Cuisines and Music, Indigenous sports, Adventure sports as well as the scenic natural beauty of the Manipur. Sangai Festival is celebrated at Keibul Lamjao & Loktak Lake, Hapte Kangjeibung and Bheigyachandra Open Air Theatre, Mapal Kangjeibung and Khuman Lampak, Kangshang, Trade & Permanent Exhibition Centre at Lamboi Khongnangkhong.
21 नवंबर से 30 नवंबर तक, मणिपुर पर्यटन विभाग ने एक वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार आयोजित किया जिसे "संगाई फेस्टिवल" कहा जाता है और जिसे पहले "पर्यटन उत्सव" के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर मणिपुर के राज्य पशु 'संगाई हिरण' के नाम पर रखा गया। मणिपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए संगाई महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव संस्कृति, हथकरघा, हस्तकला और ललित कला, व्यंजन और संगीत, स्वदेशी खेल, साहसिक खेल के साथ-साथ मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता का प्रदर्शन करता है। संगाई महोत्सव काइबुल लैमजाओ और लोकतक झील, हप्ते कांगजीबंग और भगीचंद्र ओपन एयर थियेटर, मैपल कांगजीबंग और खुमान लंपक, कंगशांग, व्यापार और स्थायी प्रदर्शनी केंद्र में लम्बोई खोंगनंगखोंग में मनाया जाता है।

14.A

- Consumer Welfare Fund is created under section 57 of the CGST Act,2017.
- **Undue benefits made by businesses under the GST law have to be deposited in the fund, in case it cannot be passed on the identified recipient.**
- As per the GST anti-profiteering rules, the Centre and the 'concerned state' has been empowered to equally share the amount deposited by erring businesses in the consumer welfare fund. 'Concerned state' would mean the state where the anti-profiteering authority has passed its order against the businesses.
- The proceeds from the consumer welfare fund, constituted under Goods and Services Tax (GST), can be given as a grant to the Centre and state governments as well as regulatory authorities.
- उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 57 के तहत किया गया है।
- **GST कानून के तहत प्रावधान है कि यदि व्यवसायों द्वारा निर्मित अनुचित लाभों को उनके चिह्नित प्राप्तकर्ता (जो उसको प्राप्त करने की पात्रता रखता हो) तक न पहुँचाया जा सके तो उसे उपर्युक्त कोष में जमा करा दिया जाए।**
- GST मुनाफाखोरी-रोधी नियमों के अनुसार, केंद्र और 'संबंधित राज्य' को दोषी व्यवसायों द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करायी गयी राशि को समान रूप से साझा करने हेतु सशक्त बनाया गया है। 'सम्बन्धित राज्य' से तात्पर्य उस राज्य से होगा जहां मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण ने ऐसे व्यवसायों के विरुद्ध अपना आदेश पारित किया हो।
- वस्तु और सेवा कर (GST) के तहत गठित उपभोक्ता कल्याण कोष से प्राप्त आय, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ नियामक प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में दी जा सकती है।

15.A

On 29th and 30th November 2018, the Indian Owl Festival, India's first owl fest, was held at Pingori village in Purandar taluka of Pune, Maharashtra. The festival was organised by Ela Foundation. It created awareness on owl conservation and feature art forms like pictures, paintings, lanterns, lamp shades, posters, origami, stitched articles, poems and stories on owls. The festival featured skits and short films on owls. Out of the 262 species of owls that are found in the world, 75 are threatened. As per a report of Traffic India, a wildlife trade monitoring body, and the World Wildlife Fund (WWF) in 2010, owls were found to be consumed and traded for black magic, street performances, taxidermy, private aviaries/zoos, food, folk medicines, etc. They are protected under the Wildlife (Protection) Act of India.
29 और 30 नवंबर 2018 को पहला, भारतीय उल्लू महोत्सव, पुणे के पुरंदर तालुका के पिंगोरी गांव में आयोजित किया गया था। त्योहार इला फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इसने उल्लू संरक्षण पर जागरूकता पैदा की और उल्लू पर कला रूपों जैसे चित्र, चित्रकला, लालटेन, दीपक रंग, पोस्टर, ओरिगामी, सिलाई वाले लेख, कविताओं और कहानियों का प्रदर्शन किया। त्यौहार में उल्लू पर स्कीट और लघु फिल्में शामिल हैं। दुनिया में पाए जाने वाले उल्लू की 262 प्रजातियों में से 75 खतरे में है। ट्रैफिक इंडिया, एक वन्यजीव व्यापार निगरानी निकाय और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की 2010 में एक रिपोर्ट के अनुसार, उल्लू को काले जादू, सड़क प्रदर्शन, टैक्सीडर्मी, निजी aviaries / चिड़ियाघर, भोजन, दवाएं, आदि के लिए उपभोग और व्यापार किया जाता है। वे भारत के वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित हैं।

16.A

The National Festival for Children of Child Care Institutions (CCIs) – "Hausla 2018" of the Ministry of Women and Child Development (MWCD) was held at Jawahar Lal Nehru Stadium in New Delhi. It was a 4 day event, from 26 to 29th November 2018. Smt Maneka Sanjay Gandhi, Union Minister for Ministry of Women and Child Development and Ms. Mary Kom, Indian Olympic Boxer & Member of Parliament (Rajya Sabha) addressed the opening ceremony. The festival witnessed participation of more than 600 Children drawn from CCIs from 16 states in the various events like painting competition,debate, athletics meet, football, chess competition Safe Neighbourhood Project making activity

and speech writing as part of the Festival. The theme for the event was "Child Safety". The Childline India Foundation (CIF) and National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) will be assisting the Ministry in organizing the events. The concluding ceremony was organized on 29th November (evening) at Siri Fort Auditorium, New Delhi in which a cultural programme by the children of CCIs, presentation of Best State Team Award based on performance during Hausla 2018 and Prize distribution to all winners of each individual category was held.
बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय उत्सव (सीसीआई) "हौसला 2018" – नई दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा आयोजित किया गया था। यह 26 से 29 नवंबर 2018 तक 4 दिवसीय कार्यक्रम था। श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री और सुश्री मैरी कॉम, भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज और संसद सदस्य (राज्य सभा) ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस उत्सव में चित्रकला प्रतियोगिता, बहस, एथलेटिक्स बैठक, फुटबॉल, शतरंज प्रतियोगिता सुरक्षित पड़ोस परियोजना बनाने और समारोह के हिस्से के रूप में भाषण लेखन जैसी विभिन्न कार्यकर्मों में 16 राज्यों से सीसीआई से 600 से अधिक बच्चों की भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम के लिए विषय "बाल सुरक्षा" था। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) और राष्ट्रीय सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) कार्यक्रमों के आयोजन में मंत्रालय की सहायता करेगा। समापन समारोह 29 नवंबर (शाम) को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें सीसीआई के बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, "हौसला 2018" के दौरान प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ राज्य टीम पुरस्कार की प्रस्तुति और व्यक्तिगत श्रेणी के सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया था।

17.B

- **Statement 1 is not correct and statement 2 is correct:** Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has recently launched Rs 1100 crore ambitious National Agricultural Higher Education Project (NAHEP) to attract talent and strengthen higher agricultural education in the country. NAHEP has been formulated with a focus to improve and sustain quality of higher agricultural education. It aims to produce a globally competitive agricultural human resource capable of developing newer technologies and skills for scale up and transfer of new technologies to improve the production system and value addition.
- **Statement 3 is not correct:** This project will be funded by the World Bank and the Indian Government on a 50:50 basis.
- **कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने हाल ही में देश में प्रतिभा को आकर्षित करने और उच्चतर कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु 1100 करोड़ रुपये की राशि के महत्वाकांक्षी *नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट* (National Agricultural Higher Education Project: NAHEP) का शुभारम्भ किया है। NAHEP को उच्चतर कृषि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादन प्रणाली और मूल्य संवर्धन में सुधार हेतु नई प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए नई प्रौद्योगिकियों और कौशल को विकसित करने में सक्षम एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कृषि मानव संसाधन का निर्माण करना है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** इस परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा।

18.B

The 19th Hornbill Festival 2018 is celebrated from 1st to 10th December 2018 in Nagaland. It is celebrated at the Naga Heritage Village in Kisama, located around 12 kilometers from the capital of the Nagaland, Kohima. The Hornbill Festival is one of the most cherished festivals of Nagaland. It is named after Hornbill, one of the most venerated bird species in the state. The 10-day festival is celebrated annually during the first week of December, i.e. from December 1-10. It is organized by State Tourism and Arts and Culture Department, Government of Nagaland to encourage inter-tribal harmony and promote culture and traditions of the different tribes of the state.
19वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2018 नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2018 तक मनाया जा रहा है। यह किसामा में नागा हेरिटेज गांव में मनाया जाता है, जो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के सबसे खूबसूरत त्यौहारों में से एक है। इसका नाम हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो राज्य में सबसे सम्मानित पक्षी प्रजातियों में से एक है। 10-दिवसीय त्यौहार दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान वार्षिक रूप से मनाया जाता है, यानि दिसंबर 1 से 10 तक। यह राज्य पर्यटन और कला व संस्कृति विभाग, नागालैंड सरकार द्वारा अंतर-जनजातीय सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए और राज्य की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है।

19.D

India's first international indigenous film festival will take place in February next year in Odisha. It will be an initiative of activist film collective 'Video Republic'. The three-stop event will kick off in Bhubaneswar on February 19 and 20, moving on to Puri from February 21 to 23 and will eventually culminate in an interaction with the adivasi communities at Niyamgiri. Films made by indigenous people or made by non-indigenous filmmakers in collaboration with the indigenous communities will be shown in the event.

भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी फिल्म त्यौहार ओडिशा में आयोजित होगा। यह कार्यकर्ता फिल्म सामूहिक 'वीडियो रिपब्लिक' की पहल होगी। तीन-स्टॉप इवेंट भुवनेश्वर में 19 फरवरी और 20 फरवरी को शुरू हो जायेंगे, जो 21 फरवरी से 23 फरवरी तक पुरी पहुंच जायेंगे और अंत में नियमगिरि के आदिवासी समुदायों के साथ वार्तालाप के साथ समाप्त हो जाएगा। स्वदेशी लोगों द्वारा बनाई गई फिल्मों या स्वदेशी समुदायों के सहयोग से गैर-स्वदेशी फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों को कार्यक्रम में दिखाया जाएगा।

20.D

- Leprosy is a chronic infectious disease **caused by Mycobacterium leprae**, an acid-fast, rod-shaped bacillus. M. leprae multiplies slowly and the incubation period of the disease, on average, is 5 years. In some cases, symptoms may occur within 1 year but can also take as long as 20 years to occur.
- **Leprosy is primarily a disease of the skin and nerves**. It mainly affects the skin, the peripheral nerves, mucosa of the upper respiratory tract, and the eyes. Leprosy is curable and treatment in the early stages can prevent disability.
- Analysis of geographical distribution of leprosy by World Health Organization (WHO) shows that **India accounted for the largest number of cases of leprosy at 60% of the global new cases reported during 2015 by 136 countries**.
- **Hence both the statements are not correct.**
- कुष्ठरोग एक दीर्घकालिक (chronic) संक्रामक रोग है, जो **माइकोबैक्टीरियम लेप्री** नामक एक एसिड-फास्ट और छड़ के आकार वाले **बैक्टीरिया** के माध्यम से होता है। **लेप्री** मंद गति से द्विगुणित होता है अतः इस रोग की उद्भवन अवधि औसतन 5 वर्षों की होती है। कुछ मामलों में लक्षण एक वर्ष में भी प्रकट हो जाते हैं जबकि कुछ में यह अवधि 20 वर्षों तक भी हो सकती है।
- **कुष्ठरोग मुख्यतः त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करने वाला रोग है।** मुख्य रूप से यह त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन तंत्र की श्लेष्मा तथा आँखों को प्रभावित करता है। कुष्ठरोग का उपचार संभव है तथा प्रारम्भिक चरणों में इसका उपचार किये जाने से अक्षमता को रोका जा सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए कुष्ठरोग के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण यह दर्शाता है कि **वर्ष 2015 के दौरान वैश्विक स्तर पर 136 देशों में दर्ज किए गए कुष्ठरोग के कुल नए मामलों में से 60% मामले भारत में दर्ज किये गए थे।**
- **इसलिए दोनों कथन सही नहीं हैं।**

21.C

The Ministry of Road Transport and Highways has inventorized 1,72,517 bridges/structures under Indian Bridge Management System (IBMS). IBMS is the largest platform in the world owned by a single owner, with database that could exceed 1,50,000 bridge structures.

In addition to the structural rating, the bridges are also being assigned Socio-Economic Bridge Rating Number which will decide the importance of the structure in relation to its contribution to daily socio-economic activity of the area in its vicinity.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (IBMS) के तहत 1,72,517 पुलों / संरचनाओं का निर्माण किया है। IBMS एक एकल स्वामित्व वाला विश्व का सबसे बड़ा मंच है, जिसका डेटाबेस 1,50,000 पुल संरचनाओं से अधिक हो सकता है। संरचनात्मक रेटिंग के अलावा, पुलों को सोशियो-इकोनॉमिक ब्रिज रेटिंग नंबर भी दिया जा रहा है, जो इसके आसपास के क्षेत्र की दैनिक सामाजिक-आर्थिक गतिविधि में इसके योगदान के संबंध में संरचना के महत्व को तय करेगा।

22.A

India is facing a major malnutrition crisis as it holds almost a One third of the world's stunted children, according to a Global Nutrition Report 2018.The report classifies India as experiencing two forms of malnutrition anemia and stunting. Stunting or low height for age is caused by long term insufficient nutrient-intake and frequent infections. With 46.6 million children who are stunted, India tops the list among 140 countries followed by Nigeria (13.3 million) and Pakistan (10.7 million). The World health organization is a Global Nutrition Report Partner.

ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत को एक बड़े कुपोषण संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह विश्व के लगभग एक तिहाई स्टंटिंग या कम ऊंचाई बच्चों को रखता है। रिपोर्ट भारत को कुपोषण के दो रूपों एनीमिया और स्टंटिंग का अनुभव करने के रूप में वर्गीकृत करती है। उम्र से कम ऊंचाई या स्टंटिंग लंबे समय तक अपर्याप्त पोषक तत्व-सेवन और लगातार संक्रमण के कारण होती है। 140 देशों में भारत में 46.6 मिलियन स्टंटिंग से ग्रसित बच्चों के साथ प्रथम स्थान पर है और उसके बाद नाइजीरिया (13.3 मिलियन) और पाकिस्तान (10.7 मिलियन) के बीच सूची में है।विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक पोषण रिपोर्ट का एक भागीदार है।

23.C

A report by UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) which was released ahead of AIDS day estimated that 1,20,000 children and adolescents aged 0-19 were living with HIV in India in 2017, the highest number in South Asia. The report titled 'Children, HIV and AIDS: The World in 2030' warned that around 80

adolescents will be dying of AIDS every day globally by 2030 if progress in preventing transmission is not accelerated. In India, an estimated 120,000 children and adolescents aged 0-19 were living with HIV in 2017. In Pakistan, this number was 5800, followed by Nepal (1,600) and Bangladesh (less than 1,000). In 2017, the estimated number of children under 5 years old newly diagnosed with HIV was 43 per cent lower than the comparable estimate in 2010 a decline greater than the 35 per cent recorded globally. "The report makes it clear, without the shadow of a doubt, that the world is off track when it comes to ending AIDS among children and adolescents by 2030," said UNICEF chief Henrietta Fore.

यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि) की एक रिपोर्ट जिसे एड्स दिवस से पहले जारी किया गया था, का अनुमान है कि 2017 में 1,20,000 , 0-19 वर्ष के बच्चे और किशोर भारत में एचआईवी के साथ रह रहे थे, जोकि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। 'चिल्ड्रेन, एचआईवी और एड्स: द वर्ल्ड इन 2030' नामक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ट्रांसमिशन को रोकने में प्रगति तेज नहीं होने पर वैश्विक रूप से 2030 तक करीब 80 किशोर प्रति दिन एड्स से मर जाएंगे। भारत में, 2017 में अनुमानित 120,000 बच्चे और किशोर एचआईवी के साथ रह रहे थे। पाकिस्तान में, यह संख्या 5800 थी, इसके बाद नेपाल (1,600) और बांग्लादेश (1,000 से कम) थे। 2017 में, एचआईवी के साथ पहचान किए गए 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अनुमानित संख्या 2010 में तुलनात्मक अनुमान के मुकाबले 43 प्रतिशत कम थी, जो विश्व स्तर पर 35 प्रतिशत कमी दर्ज की गई थी। यूनिसेफ के प्रमुख हेनरीएटा फोर ने कहा, "रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट करती है कि बिना किसी संदेह के, विश्व उस ट्रैक पर नहीं है जहां 2030 तक बच्चों और किशोरों के बीच एड्स समाप्त करने की बात आती है।"

24.C

Australia became the first country in the world to criminalize the act of falsely inducing children into orphanages as a form of slavery. The Modern Slavery Bill was passed by both houses of parliament and under it the new law, so-called "orphanage trafficking" will be treated as a slavery and trafficking offense. Evidence shows that about 80 percent of these children have family who could care for them if they had the right support.

ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बन गया जिसने दासता के रूप में अनाथाश्रम में बच्चों द्वारा किए गए कार्य को अपराध घोषित किया है। आधुनिक दासता विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत नया कानून, तथाकथित "अनाथालय तस्करी" को दासता और तस्करी अपराध के रूप में माना जाएगा। साक्ष्य दर्शाते हैं कि इन बच्चों में से 80 प्रतिशत के परिवार है जो उनके लिए सही समर्थन कर सकते है।

25.D

Dhola-Sadiya Bridge is the longest road bridge on Lohit River connecting the northeast states of Assam and Arunachal Pradesh. Longest rail-road bridge is Bogibeel in Assam.

ढोला-सदिया पुल लोहित नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल है जो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सबसे लंबा रेल-सड़क पुल असम में बोगीबील है।

26.C

Blue Flag certification — the tag given to environment-friendly and clean beaches, equipped with amenities of international standards for tourists. The Chandrabhaga beach on the Konark coast of Odisha is the first in Asia to get the Blue Flag certification.

ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण - पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया टैग, जो पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से सुसज्जित है। ओडिशा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला स्थान है।

27.D

Ease of Living Index is A Transformative Initiative of The Ministry to Help Cities Assess their Liveability Vis-À-Vis National & Global Benchmarks. "The 'Ease of Living' Index seeks to assist cities in undertaking a 360-degree assessment of their strengths, weaknesses, opportunities, and threats".

Ease of Living Index, शहरों के लिवबिलिटी के साथ -साथ नेशनल और ग्लोबल बेंचमार्क का आकलन करने में मदद करने के लिए मंत्रालय की एक परिवर्तनकारी पहल है। "Ease of Living 'इंडेक्स शहरों में उनकी क्षमता, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के बारे में 360 डिग्री का आकलन करने में शहरों की सहायता करना चाहता है।"

28.C

The Virtual ID is a random 16-digit number.

- The ID can be generated as many time as possible.
- The older ID gets automatically cancelled once a fresh one is generated.
- Users can go to the UIDAI website to generate their virtual ID which will be valid for a defined period of time, or till the user decides to change it.

- The ID, along with the biometrics of the user, would give any authorised agency, like a mobile company, limited details like name, address and photograph, which are enough for any verification.
- Agencies that undertake authentication would not be allowed to generate the Virtual ID on behalf of the user.
- UIDAI also introduced the concept of 'limited KYC', which will provide need-based or limited details of a user to an authorised agency providing a particular service.
- One's Aadhaar number cannot be derived from the Virtual ID that is generated.

वर्चुअल आईडी एक यादृच्छिक 16-अंकीय संख्या है।

- जितनी बार संभव हो उतनी बार आईडी जनरेट की जा सकती है।
- पुरानी आईडी स्वचालित रूप से रद्द हो जाती है जब एक एक नई उत्पन्न होती है।
- उपयोगकर्ता अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि निर्धारित समय अवधि के लिए मान्य होगी, या जब तक उपयोगकर्ता इसे बदलने का निर्णय नहीं लेता।
- आईडी, उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक्स के साथ, किसी भी अधिकृत एजेंसी को, मोबाइल कंपनी की तरह, नाम, पता और फोटोग्राफ जैसी सीमित जानकारी देगा, जो किसी भी सत्यापन के लिए पर्याप्त हैं।
- प्रमाणन का कार्य करने वाली एजेंसियों को उपयोगकर्ता की ओर से वर्चुअल आईडी जनरेट करने की अनुमति नहीं होगी।
- यूआईडीएआई ने ID सीमित केवाईसी 'की अवधारणा को भी पेश किया, जो किसी विशेष सेवा प्रदान करने वाली अधिकृत एजेंसी को उपयोगकर्ता की आवश्यकता-आधारित या सीमित विवरण प्रदान करेगा।
- किसी के आधार नंबर को उत्पन्न की गई वर्चुअल आईडी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

29.A

PARIVESH (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub) is an environmental single window hub for Environment, Forest, Wildlife and CRZ clearances from Central, State and district-level authorities.

- The system has been designed, developed and hosted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, with technical support from National Informatics Centre, (NIC).

PARIVESH (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub) केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और CRZ संबंधी मंजूरी के लिए एक पर्यावरणीय एकल खिड़की हब है।

- इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, (एनआईसी) से तकनीकी सहायता के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है।

30.A

On 1st December 2018, The Special Forces of India and United States completed the final maneuvers of their three-day tactical exercise called 'Vajra Kayaa' which is part of their joint military drill 'Vajra Prahar 2018' in Jaipur. Vajra Kayaa was based on narrative of an imaginary country going into a civil war due to weak democratic structure and which has now been taken over by armed terrorists.

1 दिसंबर 2018 को, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बल ने 'वज्र काया' नामक अपने तीन दिवसीय सामरिक अभ्यास के अंतिम युद्धाभ्यास को पूरा किया जो जयपुर में उनके संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार 2018' का हिस्सा है। 'वज्र काया' कमजोर लोकतांत्रिक ढांचे के कारण गृहयुद्ध से गुजर रहे एक काल्पनिक देश की कथा पर आधारित था और जिसे अब सशस्त्र आतंकवादियों ने अधिग्रहित कर लिया है।

31.C

The exchange is done each year on January 1, under the Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations and Facilities, also referred to as the Non-Nuclear Aggression Agreement.

The agreement, which was signed on December 31, 1988, and entered into force on January 27, 1991, provides that the two countries inform each other of nuclear installations and facilities to be covered under the pact on the first of January of every calendar year.

एक्सचेंज प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं के विरुद्ध आक्रमण के निषेध पर समझौते के तहत किया जाता है, जिसे गैर-परमाणु समझौता करार भी कहा जाता है।

यह समझौता, जिसे 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षरित किया गया था और 27 जनवरी, 1991 को लागू हुआ, दोनों देशों ने कहा कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को कवर करने के लिए सूचित करेंगे।

32.A

A six-member committee has been constituted by the government which will look at selling as many as 149 small and marginal oil and gas fields of state-owned ONGC and Oil India to private and foreign companies to boost domestic output. The committee will be headed by NITI Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar and includes Cabinet Secretary P K Sinha, Economic Affairs Secretary Subhash Chandra Garg, Oil Secretary M M Kutty, NITI Aayog CEO Amitabh Kant and ONGC Chairman and Managing Director Shashi Shanker. Earlier on 12th October, Prime Minister Narendra Modi called a meeting to review domestic production profile of oil and gas and the roadmap for cutting import dependence by 10 per cent by 2022 and this committee is a follow up of that meeting.

सरकार द्वारा छः सदस्यीय समिति गठित की गई है जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निजी और विदेशी कंपनियों को सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के 149 छोटे और सीमांत तेल और गैस क्षेत्रों को बेचने पर विचार करेगी। समीति का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे और इसमें कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा, आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, तेल सचिव एम एम कुट्टी, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और ओएनजीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शशि शंकर शामिल होंगे। इससे पहले 12 अक्टूबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल और गैस की घरेलू उत्पादन प्रोफ़ाइल और 2022 तक आयात निर्भरता में 10 प्रतिशत की कटौती के लिए रोडमैप की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी और यह समिति उस बैठक की अनुवर्ती है।

33.A

India's first locomotive-less train named Train 18, crossed the 180 kmph speed limit during a test run in the Kota-Sawai Madhopur section. Train 18 will become India's fastest train when it is made operational. This train has been developed indigenously, costing Rs 100 crore. It is a high-tech, energy-efficient, self-propelled (engine-less) train. It features aerodynamically designed driver cabins at both ends for quicker turn-around at destinations. It has an advanced regenerative braking system to save power. It is fully air-conditioned. It has 16 coaches. Train 18 is expected to start its commercial run from January 2019. It is expected to replace the current Shatabdi Express. Integral Coach Factory (ICF) will launch one more Train 18 this fiscal and 4 by the next fiscal.

ट्रेन 18 नामक भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन, कोटा-सवाई माधोपुर सेक्शन में परीक्षण चालन के दौरान 180 किमी प्रति घंटे की गति सीमा पार कर गई। संचालित होने पर ट्रेन 18 भारत की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी। इस ट्रेन को देश में विकसित किया गया है, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये है। यह एक उच्च तकनीक, ऊर्जा कुशल, स्व-चालित (बिना इंजन की) ट्रेन है। इसमें गंतव्य पर दोनों सिरों पर वायुगतिकीय रूप से डिज़ाइन किए गए ड्राइवर केबिन हैं। बिजली बचाने के लिए इसमें एक उन्नत पुनरुत्थान ब्रेकिंग सिस्टम है। यह पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसमें 16 कोच हैं। ट्रेन 18 के जनवरी 2019 से अपना वाणिज्यिक सफर शुरू करने की उम्मीद है। इससे मौजूदा शताब्दी एक्सप्रेस को बदलने की उम्मीद है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) इस वित्त वर्ष में एक और ट्रैन 18 और अगले वित्त वर्ष में 4 और ट्रेन लॉन्च करेगी।

34.D

an international workshop on "Developing a Ganga Museum Concept: Exchanging Experiences and Ideas between India and Europe" was held in New Delhi. The workshop was organized by National Mission for Clean Ganga (NMCG) along with GIZ India, as a part of Indo German Development Co-operation. Experts from India and the European Union participated. NMCG is planning to set up a Ganga Exhibition and a Ganga Museum for public outreach, portraying river Ganga's history and mythology, its importance for the livelihood of a huge population, and efforts for Ganga Rejuvenation. In the workshop, ideas and experiences related to the proposed Ganga Museum and Ganga Exhibition, were discussed.

"एक गंगा संग्रहालय अवधारणा का विकास: भारत और यूरोप के बीच अनुभव और विचारों का आदान-प्रदान" पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)द्वारा इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन के एक हिस्से के रूप में, जीआईजेड इंडिया के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें भारत और यूरोपीय संघ के विशेषज्ञों ने भाग लिया। एनएमसीजी सार्वजनिक पहुंच के लिए गंगा प्रदर्शनी और गंगा संग्रहालय को स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसमें गंगा के इतिहास और पौराणिक कथाओं, विशाल आबादी की आजीविका के लिए इसका महत्व, और गंगा कायाकल्प के प्रयासों को चित्रित किया गया है। कार्यशाला में, प्रस्तावित गंगा संग्रहालय और गंगा प्रदर्शनी से संबंधित विचारों और अनुभवों पर चर्चा की गई।

35.D

Qatar announced that it was quitting Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) from January 2019. The decision meant Doha could focus on cementing its position as the world's top liquefied natural gas (LNG) exporter. Doha is one of the smallest oil producers in OPEC.

कतर ने घोषणा की कि वह जनवरी 2019 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) को छोड़ रहा है। निर्णय का अर्थ है कि कतर दुनिया के शीर्ष तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। कतर ओपेक में सबसे छोटे तेल उत्पादकों में से एक है।

36 .D

Bharatmala Project is the second largest highways construction project in the country since NHDP, under which almost 50,000 km or highway roads were targeted across the country.
It includes development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes, National Corridor Efficiency Improvement, Border and International connectivity roads, Coastal and Port connectivity roads and Green-field expressways.
Highlights:

- Improvement in efficiency of existing corridors through development of Multimodal Logistics Parks and elimination of choke point
- Enhance focus on improving connectivity in North East and leveraging synergies with Inland Waterways
- Emphasis on use of technology & scientific planning for Project Preparation and Asset Monitoring
- Delegation of powers to expedite project delivery – Phase I to complete by 2022
- Improving connectivity in the North East

भारतमाला परियोजना, NHDP के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना है, जिसके तहत लगभग 50,000 किलोमीटर राजमार्ग सड़कों को देश भर में लक्षित किया गया था।
इसमें आर्थिक गलियारे, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कों और ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे का विकास शामिल है।
मुख्य विशेषताएं:

- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और चेक प्वाइंट के उन्मूलन के माध्यम से मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार
- नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और इनलैंड वाटरवेज के साथ तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दें
- परियोजना की तैयारी और संपत्ति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक योजना के उपयोग पर जोर
- परियोजना वितरण में तेजी लाने के लिए कार्यों का प्रत्यायोजन - प्रथम चरण 2022 तक पूरा करना
- नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी में सुधार

37.C
The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), India is a quasi-judicial commission in India which was set up in 1988 under the Consumer Protection Act of 1986. Its head office is in New Delhi. The commission is headed by a sitting or retired judge of the Supreme Court of India.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC), भारत में एक अर्ध-न्यायिक आयोग है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। इस आयोग की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग या रिटायर्ड जज करते हैं।
38.D
According to the Citizenship Act (1955), an illegal immigrant is defined as a person who enters India without a valid passport or stays in the country after the expiry of the visa permit. Also, the immigrant who uses false documents for the immigration process.
नागरिकता अधिनियम (1955) के अनुसार, एक अवैध अप्रवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वैध पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश करता है या वीजा परमिट की समाप्ति के बाद देश में रहता है। इसके अलावा, अप्रवासी जो आव्रजन प्रक्रिया के लिए झूठे दस्तावेजों का उपयोग करता है।
39.D
The provincial Khyber Pakhtunkhwa government in northwest Pakistan has declared the ancient Hindu religious site of Panj Tirath in Peshawar as national heritage.
उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में प्रांतीय खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पेशावर में पंज तीरथ के प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है।
40.B
To reduce losses due to non-payment of electricity bills and also promote solar energy, Maharashtra state government has launched Atal Solar Krishi Pump Yojana.

- Under the scheme, the government of Maharashtra has decided to give two LED bulbs, a DC fan and a mobile charging socket as freebies to farmers.
- The scheme provides a subsidy of up to 95% on solar pumpsets. The State plans to install one lakh solar pumps.

बिजली के बिलों का भुगतान न करने के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अटल सौर कृषि पंप योजना शुरू की है।

- इस योजना के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को मुफ्त में दो एलईडी बल्ब, एक डीसी पंखा और एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट देने का फैसला किया है।
- योजना सौर पंपसेट पर 95% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। राज्य में एक लाख सोलर पंप लगाने की योजना है।

41.C

Street Light National Programme is an initiative of the Government to promote energy efficiency in the country. Government aims to replace 3.5 crore conventional street lights with energy efficient LED lights.
Energy Efficiency Services Limited, a Public Energy Services Company under the administration of **Ministry of Power**, Government of India (GoI) is the implementing agency for SLNP.
स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है। सरकार का लक्ष्य 3.5 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट्स से बदलना है।
ऊर्जा दक्षता सर्विसेस लिमिटेड, भारत सरकार के **ऊर्जा मंत्रालय** के प्रशासन के तहत एक सार्वजनिक ऊर्जा सेवा कंपनी, एसएलएनपी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

42.C

The Climate Change Performance Index (CCPI) is an annual publication by Germanwatch, and Climate Action Network Europe. It evaluates the climate protection performance of 58 countries, responsible for over 90% of global energy-related CO2 emissions.
क्लाइमेट चैंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) जर्मनवाच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है। यह वैश्विक ऊर्जा से संबंधित 90% से अधिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 58 देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

43.A

China has developed a massive bomb, said to be the country's answer to the US-built 'Mother of All Bombs', the most powerful non-nuclear weapon.

- It is dubbed as the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons.
- To match the U.S. weapon, Russia developed the "Father of All Bombs" which is both bigger and thermobaric, meaning it uses gas to create a huge fireball rather than a shockwave.

चीन ने एक विशाल बम विकसित किया है, जिसे अमेरिका द्वारा निर्मित बम 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ' जो सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु हथियार का चीन द्वारा प्रतिउत्तर कहा जा रहा है।

- इसकी विशाल विनाशक क्षमता के कारण "मदर ऑफ ऑल बॉम्स" के चीनी संस्करण के रूप में डब किया गया है, जिसका दावा है कि यह परमाणु हथियारों के पश्चात् सबसे घातक है।
- अमेरिकी हथियार से बराबरी के लिए, रूस ने "फादर ऑफ ऑल बॉम्स" विकसित किया, जो बड़ा और थर्मोबैरिक दोनों है, इसका मतलब है कि यह केवल एक शॉकवेव के बजाय एक विशाल आग का गोला बनाने के लिए गैस का उपयोग करता है।

44.A

CIMON (Crew Interactive Mobile Companion), the first Artificial Intelligence (AI) powered robot to fly in Space, was launched to the International Space Station (ISS) . German astronaut Alexander Gerst talked with the artificially intelligent crew-assistant CIMON during a 90-minute experiment, aboard the International Space Station (ISS).
सीमोन (क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपैनियन), अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित रोबोट है ,जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन(आईएसएस) में लॉन्च किया गया था। जर्मन अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गेर्स्ट ने कृत्रिम बुद्धिमान चालक दल-सहायक सीमोन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में 90 मिनट के प्रयोग के दौरान बात की।

45.C

A rare disease, also referred to as an orphan disease, is any disease that affects a small percentage of the population.

- Most rare diseases are genetic, and are present throughout a person's entire life, even if symptoms do not immediately appear.
- The most common rare diseases recorded in India are Haemophilia, Thalassemia, sickle-cell anaemia and primary immuno deficiency in children, auto-immune diseases, Lysosomal storage disorders such as Pompe disease, Hirschsprung disease, Gaucher's disease, Cystic Fibrosis, Hemangiomas and certain forms of muscular dystrophies.

एक दुर्लभ बीमारी, जिसे एक ऑर्फ़न डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, ऐसी कोई भी बीमारी है जो आबादी के छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती है।

- अधिकांश दुर्लभ रोग आनुवांशिक होते हैं, और किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में मौजूद होते हैं, भले ही लक्षण तुरंत प्रकट न हों।

- भारत में हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल-सेल एनीमिया और बच्चों में प्राथमिक इम्युनो की कमी, पोस्म रोग, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे कि पोम्पे रोग, हिर्शस्प्रेस रोग, गौचर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमांगीओमास और कुछ रूपों में दर्ज की गई सबसे आम दुर्लभ बीमारियां हैं।

46.C

Vijay Mallya has become the first person to be declared a fugitive offender under the Fugitive Economic Offenders Act.

- A person can be named an offender under this law if there is an arrest warrant against him or her for involvement in economic offences involving at least Rs. 100 crore or more and has fled from India to escape legal action.
- The investigating agencies have to file an application in a Special Court under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 containing details of the properties to be confiscated, and any information about the person's whereabouts.

विजय माल्या भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा अपराधी घोषित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।

- इस कानून के तहत एक व्यक्ति को एक अपराधी का नाम दिया जा सकता है यदि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आर्थिक अपराध में शामिल होने के लिए हो या कम से कम 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक तथा कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से भाग गया हो ।
- जांच एजेंसियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक विशेष अदालत में अर्जी दाखिल करनी होती है, जिसमें जब्त की जाने वाली संपत्तियों का विवरण, और व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हो।

47.D

the first 5-day bilateral air exercise "SHINYUU Maitri-18" between India and Japan, commenced at the Air Force station in Agra in Uttar Pradesh. The theme of the exercise is: 'Joint mobility and humanitarian assistance and disaster relief (HADR) on transport aircraft'. भारत और जापान के बीच "शिन्यु मैत्री -18",नामक पहला 5 दिवसीय द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास, उत्तर प्रदेश के आगरा में वायु सेना स्टेशन से शुरू हुआ। अभ्यास का विषय यह है: 'परिवहन वायुयान पर संयुक्त गतिशीलता और मानवीय सहायता व आपदा राहत (एचएडीआर)'।

48.C

The Bill amends the Citizenship Act, 1955 to make illegal migrants who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, eligible for citizenship.

- Under the Act, one of the requirements for citizenship by naturalisation is that the applicant must have resided in India during the last 12 months, and for 11 of the previous 14 years. The Bill relaxes this 11 year requirement to six years for persons belonging to the same six religions and three countries.
- The Bill provides that the registration of Overseas Citizen of India (OCI) cardholders may be cancelled if they violate any law.

विधेयक नागरिकता अधिनियम, 1955 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए संशोधन करता है।

- अधिनियम के तहत, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान लगातार और पिछले 14 वर्षों में से 11 के लिए भारत में रहना चाहिए। यह बिल समान छह धर्मों और तीन देशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए इस 11 साल की आवश्यकता को छह साल तक ही सीमित करता है।
- विधेयक यह प्रावधान करता है कि भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है यदि वे किसी कानून का उल्लंघन करते हैं।

49.B

The union Human Resource Development (HRD) ministry is compiling this schooling index.

The Index will assess states on a 1,000 point grading system with 10-20 points per parameter.

- Areas: The 70 indicators will grade state schooling systems on areas like number of existing teacher vacancies, number of direct entry recruitments especially at leadership positions, school infrastructure and so on.
- The Niti Aayog which was earlier developing its own School Education Quality Index, will be using 33 of the 70 criteria under the PGI for their own assessments.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय इस स्कूलिंग इंडेक्स का संकलन कर रहा है।

सूचकांक 10-20 अंक प्रति पैरामीटर के साथ 1,000 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम पर राज्यों का आकलन करेगा।

- क्षेत्र: 70 संकेतक मौजूदा शिक्षक रिक्तियों की संख्या, विशेष रूप से नेतृत्व के पदों पर सीधी प्रवेश भर्तियों की संख्या, स्कूल के बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर राज्य स्कूली शिक्षा प्रणालियों को ग्रेड करेंगे।
- नीति आयोग जो पहले अपने स्वयं के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक विकसित कर रहा था, पीजीआई के तहत 70 मानदंडों में से 33 का उपयोग अपने स्वयं के आकलन के लिए करेगा।

50.A

SpaceX founded by Elon Musk, launched India's first privately built satellite ExseedSAT 1 along with 63 other satellite from 18 countries from the Vandenberg air force base in California, USA. ExseedSAT 1 was built at a cost of Rs. 2 Crore by the Mumbai based Startup Exseedspace. ExseedSAT 1 which weighs around 1 kg is an open radio transponder that works on ham frequencies. The satellite will have a life span of 5 years and it will allow people to receive signals on 145.90 Mhz frequency with the help of a TV tuner.

एलन मस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में वेंडेनबर्ग वायुसेना बेस से 18 देशों के 63 अन्य उपग्रहों के साथ भारत का पहला निजी रूप से निर्मित उपग्रह 'एक्ससीड सैट 1' लॉन्च किया। 'एक्ससीड सैट 1' मुंबई आधारित स्टार्टअप एक्ससीडस्पेस द्वारा 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था।'एक्ससीड सैट 1' जो लगभग 1 किग्रा वजन का है, वह एक खुला रेडियो ट्रांसपोंडर है जो हैम आवृत्तियों पर काम करता है। उपग्रह का 5 साल का जीवन काल होगा और यह टीवी ट्यूनर की सहायता से 145.90 Mhz आवृत्ति पर सिग्नल प्राप्त करने की अनुमति देगा।

51.C

On December 4, 2018, a two-day "Conference on EU-India Partnership for Cultural Heritage Conservation" commenced at the National Museum Auditorium, Janpath, New Delhi. It concluded in December 5, 2018. Its objective is to enhance EU-India collaboration in the field of cultural heritage conservation. The conference was inaugurated by: Minster of State (I/C) Shri. Hardeep Singh Puri. As part of this, the Delegation of the European Union together with the National Museum Institute, Government of India, will convene 20 Indian and 18 European experts. It also marked the pinnacle of the European Year of Cultural Heritage (EYCH), which will conclude on December 6-7, 2018.

4 दिसंबर, 2018 को, 'सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूरोपीय संघ-भारत भागीदारी' पर दो दिवसीय "सम्मेलन" राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार, जनपथ, नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह 5 दिसंबर, 2018 को समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में यूरोपीय संघ-भारत सहयोग को बढ़ाना है। सम्मेलन का उद्घाटन राज्य मंत्री (आई / सी) श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया ।इस अवसर के हिस्से के रूप में, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, भारत सरकार मिलकर 20 भारतीय और 18 यूरोपीय विशेषज्ञों को बुलाएंगे। इसने सांस्कृतिक विरासत (ईवाईएचसी) के यूरोपीय वर्ष के शिखर को भी चिह्नित किया, जो 6-7 दिसंबर, 2018 को समाप्त होगा।

52.C

In pursuance to the goal – Housing for all by 2022, the rural housing scheme Indira Awas Yojana has been revamped to Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin and approved during March 2016. Under the scheme, financial assistance is provided for construction of pucca house to all houseless and households living in dilapidated houses. It is proposed that one crore households would be provided assistance for construction of pucca house under the project during the period from 2016-17 to 2018-19. The scheme would be implemented in rural areas throughout India except Delhi and Chandigarh. The cost of houses would be shared between Centre and States.

- Under PMAY, the cost of unit assistance is to be shared between Central and State Governments in the ratio 60:40 in plain areas and 90:10 for North Eastern and hilly states.
- The unit assistance given to beneficiaries under the programme is Rs 1,20,000 in plain areas and to Rs 1,30,000 in hilly states/difficult areas /Integrated Action Plan (IAP) for Selected Tribal and Backward Districts. Presently the NE States, States of HP, J&K and Uttarakhand and all 82 LWE districts are identified as difficult and hilly areas.
- The unit size is 25 sq.m including a dedicated area for hygienic cooking.
- The beneficiary is entitled to 90 days of unskilled labour from MGNREGA.
- The beneficiary would be facilitated to avail loan of up to Rs.70,000/- for construction of the house which is optional.
- Funds will be transferred electronically directly to the account of the beneficiary.

लक्ष्य के अनुसरण में - 2022 तक सभी के लिए आवास, ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण और मार्च 2016 के दौरान अनुमोदित की गयी है। इस योजना के तहत सभी आवासहीन और घरों में जीर्ण-शीर्ण मकान को पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रस्तावित है कि 2016-17 से 2018-19 की

अवधि के दौरान परियोजना के तहत पक्के मकान के निर्माण के लिए एक करोड़ परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। आवासों की लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाएगी।

- PMAY के तहत, इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामान्य क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जानी है।
- कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली यूनिट सहायता सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी राज्यों / कठिन क्षेत्रों / चयनित आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) में 1,30,000 रुपये है। वर्तमान में NE राज्यों, HP, J & K और उत्तराखंड और सभी 82 LWE जिलों को कठिन और पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है।
- इकाई का आकार 25 वर्गमीटर है, जिसमें हाइजेनिक खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल है।
- लाभार्थी मनरेगा से 90 दिनों के अकुशल श्रम का हकदार है।
- लाभार्थी को घर के निर्माण के लिए रु .70,000 / - तक का ऋण लेने की सुविधा होगी जो वैकल्पिक है।
- धनराशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

53.C

The Bill regulates the use of DNA technology for establishing the identity of persons in respect of matters listed in a Schedule. These include criminal matters (such as offences under the Indian Penal Code, 1860), and civil matters such as parentage disputes, emigration or immigration, and transplantation of human organs.

- The Bill establishes a National DNA Data Bank and Regional DNA Data Banks. Every Data Bank will maintain the following indices: (i) crime scene index, (ii) suspects' or undertrials' index, (iii) offenders' index, (iv) missing persons' index, and (v) unknown deceased persons' index.
- The Bill establishes a DNA Regulatory Board. Every DNA laboratory that analyses a DNA sample to establish the identity of an individual, has to be accredited by the Board.
- Written consent by individuals is required to collect DNA samples from them. Consent is not required for offences with punishment of more than seven years of imprisonment or death.
- The Bill provides for the removal of DNA profiles of suspects on filing of a police report or court order, and of undertrials on the basis of a court order. Profiles in the crime scene and missing persons' index will be removed on a written request.
- The central government will establish a National DNA Data Bank and Regional DNA Data Banks for each state, or two or more states, as it may deem necessary.

अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए विधेयक डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग को नियंत्रित करता है। इनमें आपराधिक मामले (जैसे भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध), और नागरिक मामले जैसे कि पेरेंटेज विवाद, उत्प्रवास या आप्रवास, और मानव अंगों के प्रत्यारोपण शामिल हैं।

- विधेयक एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक स्थापित करता है। प्रत्येक डेटा बैंक निम्नलिखित सूचकांकों को बनाए रखेगा: (i) अपराध दृश्य सूचकांक, (ii) संदिग्ध 'या उपक्रमों का सूचकांक, (iii) अपराधियों का सूचकांक, (iv) लापता व्यक्तियों का सूचकांक, और (v) अज्ञात मृतक व्यक्तियों का सूचकांक ।
- विधेयक एक डीएनए नियामक बोर्ड की स्थापना करता है। प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला जो किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए नमूने का विश्लेषण करती है, उसे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- व्यक्तियों द्वारा लिखित सहमति उनके लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के लिए आवश्यक है। सात साल से अधिक कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- विधेयक में पुलिस रिपोर्ट या अदालत के आदेश, और अदालतों के आदेशों के आधार पर संदिग्धों के डीएनए प्रोफाइल को हटाने का प्रावधान है। अपराध दृश्य में प्रोफाइल और गुम हुए व्यक्तियों के सूचकांक को एक लिखित अनुरोध पर हटा दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक स्थापित करेगी, यदि यह आवश्यक होता है।

54.A

55.A

according to the UN's (United Nations) World Intellectual Property Organisation (WIPO) The number of patents granted by India shot up by 50 per cent in 2017.The WIPO's "World Intellectual Property Indicators 2018" report released in Geneva. China's patent authority led the world in the number of patents granted with 420,144 and was followed by the US with 318,829. India ranked 10th in the number of patents given last year, no Indian company or university figures in last year's global list of the top 50 patent applicants. The patents granted by India increased from 8,248 in 2016 to 12,387 last year.Patents granted to foreigners accounted for 85% of the total increase. Japan's Canon ranked at the top with 24,036 patent applications during the years 2013–2015; South Korea's Samsung followed with 21,836 and China's State Grid Corporation with 21,653.

संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के अनुसार 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है । डब्ल्यूआईपीओ की "विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2018" रिपोर्ट जिनेवा में जारी की गई । चीन के पेटेंट प्राधिकरण ने 420,144 के साथ दिए गए पेटेंट की संख्या में विश्व में प्रथम रहा और इसके बाद 318,829 के साथ अमेरिका का स्थान था। पिछले साल पेटेंट की संख्या में भारत 10 वें स्थान पर रहा, पिछले साल की वैश्विक सूची में शीर्ष 50 पेटेंट आवेदकों में कोई भारतीय कंपनी या विश्वविद्यालय के आंकड़े नहीं थे। भारत द्वारा 2016 में दिए गए पेटेंट 8,248 से बढ़कर पिछले वर्ष 12,387 हो गए थे। विदेशियों को दिए गए पेटेंट कुल वृद्धि का 85% था। 2013-2015 के दौरान जापान का कैनन 24,036 पेटेंट अनुप्रयोगों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा; दक्षिण कोरिया के सैमसंग के 21,836 और चीन के राज्य ग्रिड निगम के 21,653 के साथ इसके बाद आते है।

56.B

NASA spacecraft New Horizons recently flew past the most distant world ever studied by humankind, Ultima Thule, a frozen relic of the early solar system that could reveal how planets formed.

नासा के अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स ने हाल ही में मानव जाति द्वारा अब तक के सबसे दूर के क्षेत्र, अल्टिमा थुले का अध्ययन किया, जो शुरुआती सौर मंडल के जमे हुए अवशेष है, जो यह बता सकते थे कि ग्रह कैसे बने हैं।

57.B

- Ross island – Netaji Subhash Chandra bose island
- Havelock island – Swaraj dweep
- Neil island – shaheed dweep
- रॉस द्वीप - नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
- हैवलॉक द्वीप - स्वराज द्वीप
- नील द्वीप - शहीद द्विप

58.C

The Bureau of Indian Standards(BIS) is the national Standards Body of India working under the aegis of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India.

- BIS is the National Standard Body of India established under the BIS Act 2016 for the harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental thereto.

- BIS, being a signatory to the 'Code of Good Practice for the preparation, adoption and application of standards (Article 4 of WTO-TBT Agreement, Annex 3)' has also accordingly aligned its standards formulation procedure.
- of India had launched Gold Monetization Scheme on 5th Nov.2015. BIS played an important role in finalization and implementation of the Gold Monetization Scheme in association with Department of Economic Affairs and Reserve Bank of India. Under the Gold Monetization Scheme, Assaying & Hallmarking (A&H) Centres recognized by BIS have been qualified to act as Collection and Purity Testing Centres (CPTC).

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है।

- BIS सामानों के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए है।
- बीआईएस मानकों की तैयारी, अपनाने और आवेदन के लिए the कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते (डब्ल्यूटीओ-टीबीटी समझौते के अनुच्छेद 4, अनुबंध 3) 'भी तदनुसार अपनी मानकों के निर्माण की प्रक्रिया को संशोधित किया है।
- भारत ने 5 नवंबर 2017 को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की थी। बीआईएस ने आर्थिक मामलों के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को अंतिम रूप देने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत, बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त असेंबली और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों को संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी) के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाया गया है।

59 .A

Indian Space Research Organization's (ISRO) heaviest and most-advanced high throughput communication satellite GSAT-11 was successfully launched from the Spaceport in French Guiana. The launch vehicle Ariane 5 VA-246 lifted off from Kourou Launch Base, French Guiana carrying India's GSAT-11 and South Korea's GEO-KOMPSAT-2A satellites. Ariane 5 is one of three launch vehicles operated by Arianespace along with Soyuz and Vega. The 5,854-kg GSAT-11 will provide high data rate connectivity to users of Indian mainland and islands through 32 user beams in Ku-band and 8 hub beams in Ka-band. Satellite is configured around ISRO's I-6K Bus and has a designed lifetime of more than 15 years.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सबसे भारी और सबसे उन्नत उच्च कार्यक्षमता संचार उपग्रह जीएसएटी -11 को फ्रेंच गुयाना में स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। लॉन्च वाहन एरियान 5 वीए -246 ने कौरौ लॉन्च बेस, फ्रांसीसी गुयाना से भारत के जीएसएटी -11 और दक्षिण कोरिया के जीईओ-कॉम्पसेट -2 ए उपग्रहों को लॉन्च किया। एरियान 5 सोयुज और वेगा के साथ एरियन स्पेस द्वारा संचालित तीन लॉन्च वाहनों में से एक है। 5,854 किलोग्राम जीएसएटी -11 क्यू-बैंड में 32 यूजर बीम और KA -बैंड में 8 हब बीम के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों के उपयोगकर्ताओं को उच्च डेटा दर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सैटेलाइट को इसरो की I -6 K बस (I-6K Bus) के आसपास कॉन्फ़िगर किया गया है और इसको 15 से अधिक वर्षों के जीवनकाल के डिज़ाइन किया गया है।

60.D

German firm BigRep and NOWlab produced the world's first fully functioning e-motorbike NERA using a 3D printer. The bike was conceptualised and developed in 12 weeks and includes 15 parts excluding the electrical components. It includes features like airless tires, embedded electronics, and forkless steering.

जर्मन फर्म बिगरेप और नोवलाब ने 3 डी प्रिंटर का उपयोग करके विश्व की पहली पूरी तरह से काम कर रही ई-मोटरबाइक नेरा का निर्माण किया। बाइक को 12 सप्ताह में डिजाईन और विकसित किया गया है तथा इसमें विद्युत भागों को छोड़कर 15 भाग शामिल थे। इसमें एयरलाइंस टायर, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, और फोर्कलेस स्टीयरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

61.B

a four day 1st International Conference on Bears commenced in Agra, Uttar Pradesh. Its objective was to share knowledge on principles of welfare of bears and other wild animals in zoos, sanctuaries and rescue centres. It was organized by Wildlife SOS, a conservation non-profit organisation in collaboration with Bear Care Group from the US and Canada. The conference focused on bear care, wildlife conservation and human wildlife conflict mitigation.

भालू पर चार दिन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका उद्देश्य भालू और अन्य जंगली जानवरों के कल्याण के सिद्धांतों पर ज्ञान को चिड़ियाघर,अभयारण्यों और बचाव केंद्रों में साझा करना था। यह वन्यजीव एसओएस(Wildlife SOS), एक संरक्षण गैर-लाभकारी संगठन द्वारा अमेरिका और कनाडा के भालू देखभाल समूह के सहयोग से आयोजित किया गया था। सम्मेलन में भालू देखभाल, वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष शमन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

62.C

The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) is an international and intergovernmental institution, owned and managed by its Member States, for the generation and application of early warning information. RIMES evolved from the efforts of countries in Africa and Asia, in the aftermath of the 2004 Indian Ocean tsunami, to establish a regional early warning system within a multi-hazard framework for the generation and communication of early warning information, and capacity building for preparedness and response to trans-boundary hazards. RIMES was established on 30 April 2009, and was registered with the United Nations on 1 July 2009. RIMES operates from its regional early warning center located at the campus of the Asian Institute of Technology in Pathumthani, Thailand.

अफ्रीका और एशिया के लिए क्षेत्रीय एकीकृत मल्टी-हेज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (आरआईएमईएस) एक अंतरराष्ट्रीय और अंतर सरकारी संस्था है, जो अपने सदस्य राज्यों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित की जाती है, जो शुरुआती चेतावनी की जानकारी के जनरेशन और निराकरण के लिए है। 2004 के हिंद महासागर सूनामी के बाद अफ्रीका और एशिया के देशों के प्रयासों से रिम्स विकसित हुआ, जो प्रारंभिक चेतावनी सूचना और पीढ़ी की संचार के लिए एक बहु-खतरे की रूपरेखा के भीतर एक क्षेत्रीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और सीमा-पार के खतरों पर प्रतिक्रिया की तैयारियों के लिए क्षमता निर्माण के लिए था। RIMES 30 अप्रैल 2009 को स्थापित किया गया था, और 1 जुलाई 2009 को संयुक्त राष्ट्र के साथ पंजीकृत किया गया था। RIMES का क्षेत्रीय प्रारंभिक चेतावनी केंद्र थाईलैंड के पत्थमुथनी में एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में स्थित है।

63.D

Understanding the need of timely and accurate health resources data from both public and private sector, CBHI conceptualized the framework of making a National Health Resources Repository (NHRR), where both public and private sector data resides. A national census was conceptualized in order to make a robust and comprehensive database of national health resources i.e., both public and private which inter-alia includes, hospitals, diagnostic labs, doctors and pharmacies, etc.

सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से समय और सटीक रूप से स्वास्थ्य संसाधनों के डेटा की आवश्यकता को समझते हुए, CBHI ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (NHRR) बनाने की रूपरेखा पर विचार किया है, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के डेटा होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधनों का एक मजबूत और व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जनगणना परिकल्पना की गई है, अर्थात्, सार्वजनिक और निजी दोनों जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, डॉक्टरों और फार्मेसियों आदि।

64.D

MCA21 is an e-Governance initiative of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India that enables an easy and secure access of the MCA services to the corporate entities, professionals and citizens of India.

The MCA21 application offers the following.

- Enables the business community to register a company and file statutory documents quickly and easily.
- Provides easy access of public documents
- Helps faster and effective resolution of public grievances
- Helps registration and verification of charges easily
- Ensures proactive and effective compliance with relevant laws and corporate governance
- Enables the MCA employees to deliver best of breed services

MCA21, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो भारत के कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों को MCA सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुँच के लिए सक्षम बनाता है।

MCA21 आवेदन निम्नलिखित प्रदान करता है।

- व्यवसाय समुदाय को एक कंपनी पंजीकृत करने और जल्दी तथा आसानी से वैधानिक दस्तावेज़ दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- सार्वजनिक दस्तावेजों तक आसान पहुँच प्रदान करता है
- जन शिकायतों के तेजी से और प्रभावी समाधान में मदद करता है
- आसानी से पंजीकरण और शुल्कों के सत्यापन में मदद करता है
- प्रासंगिक कानूनों और कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ सक्रिय और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करता है
- एमसीए कर्मचारियों को सुप्रशिक्षित सेवाओं का सबसे अच्छा वितरण करने में सक्षम बनाता है

65.C

The Sino-Indian Digital Collaboration Plaza (SIDCOP) has been launched by the National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) in association with Municipal Governments of Guiyang and Dalian.

- The initiative aims to bring Indian IT companies and Chinese enterprises closer to each other on a single AI enabled platform.

- It offers a boundary-less marketplace for Chinese enterprises in order to assist them in operational optimization and adopting industry best practices in business solutions by connecting with Indian enterprises.

चीन-भारतीय डिजिटल सहयोग प्लाजा (SIDCOP) को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) द्वारा गुइयांग और डालियान की नगर सरकारों के सहयोग से लॉन्च किया गया है।

- इस पहल का उद्देश्य भारतीय आईटी कंपनियों और चीनी उद्यमों को एक-दूसरे के लिए सक्षम एआई प्लेटफॉर्म पर एक-दूसरे के करीब लाना है।
- यह भारतीय उद्यमों के साथ जुड़कर परिचालन समाधानों में उनकी सहायता करने और व्यावसायिक समाधानों में उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए चीनी उद्यमों के लिए एक सीमा-रहित बाज़ार स्थल प्रदान करता है।

66.A

- Arunachal Pradesh – Abor, Mishmi, Apatani etc
- Manipur – Sema, Tangkhul etc
- Meghalaya – Chakma, Garo etc
- Mizoram – Khasi, Jantia, Kuki etc
- अरुणाचल प्रदेश - अबोर, मिशमी, अपातानी आदि
- मणिपुर - सेमा, तंगखुल आदि
- मेघालय - गारो, खासी, जयंतिया आदि
- मिजोरम - खासी, कूकी आदि

67.B

according to Oxford Economics report, the top 10 fastest growing cities in the world from 2019 to 2035 are in India. Gujarat's Surat tops the list followed by Uttar Pradesh's Agra. Surat, a diamond processing and trading center in the western state of Gujarat, will see the fastest expansion through 2035, averaging more than 9 percent. Agra and Bangalore gets 2nd and 3rd spot respectively. By 2035, the GDP of Asian countries will be 17 percent higher than all North American and European urban centers combined. Mumbai was termed as the world's 12th richest city with a total wealth of $950 billion and India is the 6th largest wealth market in the world (in terms of total wealth held) after USA, China, Japan, Germany and the UK.

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2035 तक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहर भारत में हैं। गुजरात का सूरत सूची में सबसे ऊपर है,उसके बाद उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है। गुजरात के पश्चिम में हीरा प्रसंस्करण और व्यापार केंद्र सूरत, 2035 तक सबसे तेजी से विस्तार देखेगा, जो औसतन 9 प्रतिशत से अधिक है। आगरा और बैंगलोर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 2035 तक, एशियाई देशों का सकल घरेलू उत्पाद सभी संयुक्त उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय शहरी केंद्रों की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक होगा। मुंबई को 950 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व का 12 वां सबसे अमीर शहर माना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा धन बाजार (कुल संपत्ति के मामले में) है।

68.C

India is the fourth highest emitter of carbon dioxide in the world, accounting for 7 percent of global emissions in 2017, according to a study by Global Carbon Project. The top 10 emitters were China, the US, the EU, India, Russia, Japan, Germany, Iran, Saudi Arabia and South Korea. The top four emitters in 2017, which covered 58 per cent of global emissions, were China (27 percent), the US (15 percent), the European Union (10 percent) and India (7 percent).The rest of the world contributed 41 per cent last year. India's emissions look set to continue their strong growth by an average of 6.3 per cent in 2018, with growth across all fuels including coal (7.1 percent), oil (2.9 percent) and gas (6 percent). The Indian emissions were projected to grow 2 percent in 2017, compared to 6 per cent per year averaged over the previous decade, due to significant government interventions in the economy.

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के एक अध्ययन के मुताबिक भारत 2017 में वैश्विक उत्सर्जन के 7% उत्सर्जन के साथ,विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा सबसे ज्यादा उत्सर्जक देश है। शीर्ष 10 उत्सर्जक हैं : चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, रूस, जापान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया। 2017 में शीर्ष चार उत्सर्जक, जिसमें वैश्विक उत्सर्जन का 58 प्रतिशत शामिल था, चीन (27 प्रतिशत), यूएस (15 प्रतिशत), यूरोपीय संघ (10 प्रतिशत) और भारत (7 प्रतिशत) थे। शेष विश्व ने पिछले साल 41 प्रतिशत योगदान दिया। कोयले (7.1 प्रतिशत), तेल (2.9 प्रतिशत) और गैस (6 प्रतिशत) समेत सभी ईंधन में वृद्धि के साथ 2018 में भारत के उत्सर्जन में 6.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेपों के कारण पिछले दशक में प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की तुलना में भारतीय उत्सर्जन 2017 में 2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

69.B

Hunar Haats are organised by Ministry of Minority Affairs under USTTAD (Upgrading the Skills & Training in Traditional Arts/Crafts for Development) scheme.

- The USTTAD scheme aims at preserving & promoting the rich heritage of the traditional arts & crafts of the Minority communities.
- Hunar Haats provide a platform to master artisans and craftsmen to display their rich heritage and skill, on the other hand these exhibitions bring both domestic and international markets to the artisans and craftsmen, empowering them with various resources. The National Minority Finance Development Corporation also supports them with financial aid/ loans etc.

हुनर हाट का आयोजन यूएसटीटीएडी (USTTAD) योजना के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है (पारंपरिक कला / शिल्प में विकास के लिए कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन) ।

- यूएसटीएटीएडी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है।
- हुनर हाट अपनी समृद्ध विरासत और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को एक मंच प्रदान करते हैं, दूसरी ओर ये प्रदर्शनियां कारीगरों और शिल्पकारों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में लाती हैं, उन्हें विभिन्न संसाधनों के साथ सशक्त बनाती हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम भी वित्तीय सहायता / ऋण आदि के साथ उनका समर्थन करता है।

70.C

Sikkim has announced the One family one job scheme to provide employment to the youth of Sikkim.

- The scheme entitles one government job for every family in the state.

सिक्किम के युवाओं को रोजगार देने के लिए सिक्किम ने वन परिवार, वन जॉब योजना की घोषणा की है।

- यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी प्रदान करती है।

71.C

The Strategic Central American Nation, Panama became the first Latin American Country to join China's ambitious Belt and Road Initiative after the visit of Chinese President Xi Jinping to Panama. Chinese President Xi Jinping and his Panamanian counterpart Juan Carlos Varela inked 19 separate deals during the bilateral meeting.

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय अमेरिकी राष्ट्र, पनामा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पनामा यात्रा के बाद चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट और रोड पहल में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके पैनामेनियन समकक्ष जुआन कार्लोस वेरेला ने आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान 19 अलग-अलग सौदे किए।

72.C

Under its revised mandate TRIFED has stopped bulk procurement in Minor Forest Produce (MFP) and surplus Agricultural Produce (SAP) from Tribals.

- This procurement is now done by the State-level Tribal Cooperatives Societies/Federations.
- TRIFED now functions as a 'market developer' for tribal products and as 'service provider' to its member federations.
- TRIFED is now engaged in the marketing development of tribal products (natural and organic products, handicrafts, ratification etc.) through its own shops (TRIBES India) and shops selling its products on consignment basis.

अपने संशोधित शासनादेश के तहत ट्राइफेड ने आदिवासियों से मामूली वन उपज (एमएफपी) और अधिशेष कृषि उपज (एसएपी) में थोक खरीद बंद कर दी है।

- यह खरीद अब राज्य स्तरीय जनजातीय सहकारी समितियों/ संघों द्वारा की जाती है।
- ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए 'बाजार डेवलपर' के रूप में और अपने सदस्य संघों के लिए 'सेवा प्रदाता' के रूप में कार्य करता है।
- TRIFED अब अपनी खुद की दुकानों (TRIBES India) और खेप के आधार पर अपने उत्पादों को बेचने वाली दुकानों के माध्यम से आदिवासी उत्पादों (प्राकृतिक और जैविक उत्पादों, हस्तशिल्प, अनुसमर्थन आदि) के विपणन विकास में लगी हुई है।

73.B

Formalin is a toxic, colourless solution that is derived by dissolving formaldehyde gas in water.

- It is a cancer-inducing chemical used to preserve fish and is used as a disinfectant. It is used in the manufacture of pesticides, fertilisers, glue, paper and paint, among other products.
- Formalin causes irritation in the eyes, throat, skin and stomach. In the long run continued exposure causes harm to the kidneys, liver and can even cause cancers.

- Formaldehyde is a highly reactive, flammable gas, which means it can become a fire hazard when exposed to flame or heat.

फॉर्मालिन एक विषैला, रंगहीन घोल है जो पानी में फार्मलाडिहाइड गैस को घोलकर बनाया जाता है।

- यह एक कैंसर-उत्प्रेरण रसायन है जिसका उपयोग मछली को संरक्षित करने के लिए और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अन्य उत्पादों के बीच कीटनाशकों, उर्वरकों, गोंद, कागज और पेंट के निर्माण में किया जाता है।
- फॉर्मेलिन से आंखों, गले, त्वचा और पेट में जलन होती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से किडनी, लीवर को नुकसान पहुंचता है और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है।
- फॉर्मलडिहाइड एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, ज्वलनशील गैस है, जिसका अर्थ है कि यह आग की लौ या गर्मी के संपर्क में आने पर खतरनाक हो सकता है।

74.A

On 06th December 2018, Lieutenant governors (LGs) and administrators of Union territories have been empowered by the central government to designate civil courts as special courts to adjudicate contracts relating to infrastructure projects. This comes under Section 20B of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963). According to this the state government, in consultation with the chief justice of the high court, can designate one or more civil courts as special courts within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under this Act in respect of contracts relating to infrastructure projects.

06 दिसंबर 2018 को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स (एलजी) और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचों से संबंधित परियोजनाओं का निर्णय लेने के लिए नागरिक अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। यह विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (47 of 1963) की धारा 20 बी के तहत आता है। इसके अनुसार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक या अधिक नागरिक अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नामित कर सकती है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंध के संबंध में इस अधिनियम के तहत एक मुकदमा चलाने को अधिकृत कर सकती है।

75.C

Tax reforms – Vijay Kelkar committee
Anti-corruption – Santhanam committee
कर सुधार - विजय केलकर समिति
भ्रष्टाचार विरोधी - संथानम समिति

76.A

- India skills competition is a biennial event.
- Founded in 1950, WorldSkills is the global hub for skills excellence and development. WorldSkills brings youth, industries, and educators together to give youth the chance to compete, experience, and learn how to become the best in their skill of choice. From the traditional trades to multi-skilled technology careers in the industry and service sectors, supported by partners, industries, governments, volunteers, and educational institutions, WorldSkills vision is to improve the world through the power of skills. It has 75 Member countries and regions, all working with youth, educators, governments, and industries to help prepare the workforce and talent of today for the jobs of the future
- भारत कौशल प्रतियोगिता एक द्विवार्षिक घटना है।
- 1950 में स्थापित, वर्ल्डस्किल्स कौशल उत्कृष्टता और विकास का वैश्विक केंद्र है। वर्ल्डस्किल्स युवाओं, उद्योगों और शिक्षकों को एक साथ लाता है, ताकि युवाओं को प्रतिस्पर्धा, अनुभव और अपनी पसंद के कौशल में सर्वश्रेष्ठ बनने का मौका दिया जा सके। पारंपरिक ट्रेडों से लेकर उद्योग और सेवा क्षेत्रों में बहु-कुशल प्रौद्योगिकी करियर तक, भागीदारों, उद्योगों, सरकारों, स्वयंसेवकों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा समर्थित, वर्ल्डस्किल्स विजन कौशल की शक्ति के माध्यम से विश्व को बेहतर बनाने के लिए है। इसमें 75 सदस्य देश और क्षेत्र हैं, जो सभी युवाओं, शिक्षकों, सरकारों और उद्योगों के साथ काम कर रहे हैं ताकि भविष्य के रोजगार के लिए आज के कर्मचारियों और प्रतिभाओं को तैयार करने में मदद मिल सके

77.B

The National Skills Qualifications Framework (NSQF) is a competency-based framework that organizes all qualifications according to a series of levels of knowledge, skills and aptitude.

- These levels, graded from one to ten, are defined in terms of learning outcomes which the learner must possess regardless of whether they are obtained through formal, non-formal or informal learning.
- NSQF in India was notified on 27th December 2013.

- All other frameworks, including the NVEQF (National Vocational Educational Qualification Framework) released by the Ministry of HRD, stand superceded by the NSQF.
- The NSQF is anchored at the National Skill Development Agency (NSDA) and is being implemented through the National Skills Qualifications Committee (NSQC).

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) एक योग्यता-आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं का अवलोकन करता है।

- एक से दस तक वर्गीकृत किए गए इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जिन्हें सीखने वाले को इस बात की परवाह किए बिना होना चाहिए कि वे औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं।
- भारत में NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी एनवीईक्यूएफ (राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क) सहित अन्य सभी ढांचे, एनएसक्यूएफ द्वारा संचालित हैं।
- NSQF राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) की पर्यवेक्षण संस्था है और इसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (NSQC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

78.A

- Health sector – Bhore committee & others
- Financial services for small businesses and low income household – Nachiket Mor committee
- स्वास्थ्य क्षेत्र - भोरे समिति और अन्य
- छोटे व्यवसायों और कम आय वालों के लिए वित्तीय सेवाएं - नचिकेत मोर समिति

79.D

Australia surpassed Qatar to become the world's leading exporter of Liquified Natural Gas (LNG) for the first time. This was announced according to the Australian Bureau of Statistics which stated that Australia had exported 6.55 million tonnes of LNG in November 2018 compared to Qatar's 6.27 million tonnes. LNG is Australia's third-largest export commodity behind coal and iron ore.

ऑस्ट्रेलिया ने कतर को पहली बार द्रवित प्राकृतिक गैस(एलएनजी) का दुनिया का अग्रणी निर्यातक बनने के लिए पीछे छोड़ दिया।ऑस्ट्रेलियाई ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यह घोषणा की गई थी कि कतर के 6.27 मिलियन टन की तुलना में ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2018 में 6.55 मिलियन टन एलएनजी निर्यात किया था। कोयला और लौह अयस्क के बाद एलएनजी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु है।

80.A

Malegam Committee – Micro finance

RTE amendment Bill- Key features:

- The Bill seeks to amend the Right to Education (RTE) Act to abolish the "no-detention" policy in schools. Under the current provisions of the Act, no student can be detained up to class VIII.
- As per the amendment, it would be left to the states to decide whether to continue the no-detention policy.
- The bill provides for regular examination in classes V and VIII, and if a child fails, the amendment bill grants a provision to give her or him additional opportunity to take a re-examination within two months. Such children will be provided with two-month remedial teaching to perform better in the re-examinations. If the students still do not pass the exam, the state government may decide to detain them.

मालेगाम समिति - सूक्ष्म वित्त

आरटीई संशोधन विधेयक- प्रमुख विशेषताएं:

- इस विधेयक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि स्कूलों में "नो-डिटेंशन" नीति को समाप्त किया जा सके। अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के तहत, आठवीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता है।
- संशोधन के अनुसार, **राज्यों** को यह तय करना होगा कि वे नो-डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखें या नहीं।
- विधेयक कक्षा V और VIII के लिए नियमित परीक्षा का प्रावधान करता है, और यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो संशोधन विधेयक उसे दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर देने के प्रावधान को प्रदान करता है। ऐसे बच्चों को पुन: परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दो महीने का उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाएगा। यदि छात्र अभी भी परीक्षा पास नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें उसी कक्षा में रोकने संबंधी निर्णय ले सकती है।

81.D

The Gandhi Peace Prize was instituted in the year 1995 on the occasion of the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi.

- This annual award is given to individuals and institutions for their contributions towards social, economic and political transformation through non-violence and other Gandhian methods.
- The award carries a cash prize of Rs 1 crore, a citation and a Plaque as well as an exquisite traditional handicraft/handloom item.
- The Award for every year is selected by a Jury under the Chairmanship of the Prime Minister.
- Shri Yohei Sasakawa for the year 2018 for his contribution in Leprosy Eradication in India and across the world.

गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125 वीं जयंती के अवसर पर किया गया था।

- यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके योगदान के लिए दिया जाता है।
- पुरस्कार में 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका के साथ-साथ एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला / हथकरघा वस्तु भी शामिल है।
- प्रत्येक वर्ष के लिए पुरस्कार का चयन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक जूरी द्वारा किया जाता है।
- वर्ष 2018 के लिए श्री योही ससाकावा को भारत और विश्व भर में कुष्ठ उन्मूलन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है ।

82.D

- Saksham (Sanrakshan Kshamta Mahotsav) is an annual flagship event of Petroleum Conservation Research Association (PCRA) under the aegis of Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India , with active involvement of the Oil & Gas PSUs along with other stakeholders like State Governments, for creating focused attention on fuel conservation through people centric activities and to sensitize the masses about the conservation and efficient use of petroleum products leading to better health and environment.
- Saksham (Sanrakshan Kshamta Mahotsav) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) का एक वार्षिक कार्यक्रम है। भारत, तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ राज्य सरकारों जैसे अन्य हितधारकों के साथ लोगों की केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने तथा बेहतर स्वास्थ्य और वातावरण के लिए अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और कुशल उपयोग के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए भारत की सक्रिय भागीदारी के लिए आयोजन करता है

83.B

Vice President of India Shri M.Venkaiah Naidu released two books on the compilation of selected speeches made by the President, Shri Ram Nath Kovind in the first year of assuming the office. The books are titled as, "The Republican Ethic" in English and "Loktantra ke Swar" in Hindi. The occasion was also graced by Union Minister of External Affairs, Smt. Sushma Swaraj and the Minister of Information Broadcasting (IC), Col. Rajyavardhan Singh Rathore along with other senior dignitaries. 'The Republican Ethic' is a collection of 95 select speeches in English categorized into eight subgroups — Addressing the Nation, diversity of India, window to the world, educating India, equipping India, dharma of public service, honoring our sentinels, spirit of the Law & acknowledging excellence. The book "Loktantra ke Swar" – is a collection of 109 speeches in Hindi which talks about different layers and levels of multifaceted largest democracy in the world – India and the building blocks of the book are equality, egalitarianism & education.

भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कार्यालय संभालने के पहले वर्ष में श्री राम नाथ कोविंद द्वारा चुने गए भाषणों के संकलन पर दो पुस्तकें जारी कीं। किताबों का शीर्षक अंग्रेजी में "द रिपब्लिकन एथिक" और हिंदी में "लोकतंत्र के स्वर" के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और सूचना प्रसारण मंत्री (आईसी), कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। 'द रिपब्लिकन एथिक' अंग्रेजी में 95 चयनित भाषणों का संग्रह है जो आठ उपसमूहों में वर्गीकृत है – राष्ट्र को संबोधित करना, भारत की विविधता, वैश्विक दर्शन, भारत को शिक्षित करना, भारत में क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा का धर्म, हमारे प्रेषकों का सम्मान करना, कानून की भावना और उत्कृष्टता को स्वीकार करना हैं। पुस्तक "लोकतंत्र के स्वर" – हिंदी में 109 भाषणों का संग्रह है जो विभिन्न स्तरों और विश्व में बहुसंख्यक सबसे बड़े लोकतंत्र के स्तरों के बारे में बात करती है – पुस्तक का सार भारत का निर्माण खंड, समानता, समानतावाद और शिक्षा हैं।

84.C

Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri Radha Mohan Singh announced Food and Agriculture Organisation (FAO) Council's approval to India's proposal to observe an International Year of Millets in 2023. This was approved in the 160th session of the Food and Agriculture Organisation (FAO) Council, being held in Rome.

Millets consists of Jowar, Bajra, Ragi and minor millets together termed as nutri-cereals. Earlier, India had observed 2018 as the National Year of Millets, which promoted cultivation and consumption of these nutri-cereals. This decision will thus enhance global awareness to bring back these nutri-cereals to the plate, for food and nutrition security.

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) परिषद द्वारा 2023 को 'मिलेट(मोटा अनाज) के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में आब्जर्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी की घोषणा की। इसे रोम में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) परिषद के 160 वें सत्र में अनुमोदित किया गया। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी और मामूली बाजरा होते हैं जिन्हें पोषक अनाज कहा जाता है। इससे पहले, भारत ने 2018 को मिलेट के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसने इन पोषक अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा दिया था। इस निर्णय से खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए इन पोषक तत्वों को वापस लाने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ जाएगी।

85.D

Kyasanur forest disease (KFD) is a tick-borne viral haemorrhagic fever endemic (constant presence of disease) in Karnataka State, India.

- Hard ticks (Hemaphysalis spinigera) are the reservoir of the **KFD virus** and once infected, remain so for life.
- Rodents, shrews, and monkeys are common hosts for KFDV after being bitten by an infected tick. KFDV can cause epizootics with high fatality in primates.
- Seasonality is another important risk factor as more cases are reported during the dry season, from November through June.

Kyasanur forest disease (KFD) भारत के कर्नाटक राज्य, में एक टीक-जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार एंडेमिक (बीमारी की निरंतर उपस्थिति) है।

- हार्ड टिक्स (हेमाफिसैलिस स्पिनिगेरा) केएफडी वायरस के भंडार हैं और एक बार संक्रमित होने पर, जीवन भर बने रहते हैं।
- संक्रमित टीक से काटे जाने के बाद अधिक संक्रमित होने का डर रहता है । केएफडीवी प्राइमेट्स में उच्च घातकता के साथ एपिज़ुटिक्स का कारण बन सकता है।
- नवंबर से जून तक शुष्क मौसम के दौरान महत्वपूर्ण जोखिम कारक अधिक मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

86.B

the 10th Edition of INDRA NAVY, the bilateral exercise between Indian Navy and Russian Federation Navy (RuFN) started at Vishakhapatnam. The Primary aim of the exercise is to increase interoperability amongst the two navies, develop common understanding and procedures for maritime security operations. Anti-Submarine Warfare (ASW), Air Defence Drills, Surface firings, Visit Board search and Seizure (VBSS) operations and tactical procedures will be the thrust of exercises at sea.

'इंद्रा नेवी' का 10 वां संस्करण, भारतीय नौसेना और रूसी संघ नौसेना (आरयूएफएन) के बीच द्विपक्षीय अभ्यास विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य दोनो नौ सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना है। एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू), एयर डिफेंस ड्रिल, भूतल फायरिंग, विज़िट बोर्ड सर्च और जब्त (वीबीएसएस) ऑपरेशंस और सामरिक प्रक्रियाएं समुद्र में अभ्यास का भाग होंगी।

87.C

Scientists from the Peter Grünberg Institute (PGI) in Germany made nanowire devices made from zinc oxide crystals can inherently process and even store information. Further, a memristive element was produced from nanowires by the researchers from Polytechnic University of Turin and RWTH Aachen University in Germany. These may help build bioinspired "neuromorphic" processors, able to take over the diverse functions of biological synapses and neurons. For this, scientists used a single zinc oxide nanowire measuring about a ten-thousandth of a millimeter in size. This type of nanowire is over a thousand times thinner than a human hair. The resulting memristive component not only takes up a tiny amount of space, but also is able to switch much faster than flash memory.

जर्मनी में पीटर ग्रुनबर्ग इंस्टीट्यूट (पीजीआई) के वैज्ञानिकों ने जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल से नैनोवायर डिवाइस बनाए हैं जो स्वाभाविक रूप से क्रिया कर सकते हैं और यहां तक कि जानकारी को संग्रहित भी कर सकते हैं। इसके अलावा, जर्मनी में ट्यूरिन और आरडब्ल्यूटीएच आचेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नैनोवायर से एक मेमोरी डिवाइस बनाया है। ये जैविक स्न्नाप्सेस और न्यूरॉन्स के विभिन्न कार्यों को लेने में सक्षम, जैवप्रेरित "न्यूरोमोर्फिक" प्रोसेसर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए, वैज्ञानिकों ने एक जिंक ऑक्साइड नैनोवायर का उपयोग आकार में एक मिलीमीटर के दस हजारवें भाग को मापने के लिए किया था। इस प्रकार का नैनोवायर मानव बाल की तुलना में एक हजार गुना पतला होता है। परिणामी मेमोरी डिवाइस न केवल एक छोटा स्थान लेता है, बल्कि फ्लैश मेमोरी से बहुत तेज स्विच करने में सक्षम है।

88.A

- SWAYAM is a programme initiated by Government of India and designed to achieve the three cardinal principles of Education Policy viz., access, equity and quality. The objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged.
- SWAYAM seeks to bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy.
- In order to ensure best quality content are produced and delivered, nine National Coordinators have been appointed.
- SWAYAM भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति के तीन कार्डिनल सिद्धांतों, पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण शिक्षण संसाधन प्रदान करना है।
- SWAYAM उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं।
- सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए, नौ राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।

89.C

The Indian Space Research Organisation's (ISRO) capacity-building programme on nanosatellite development, UNNATI, was inaugurated recently.

UNNATI, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, जो कि नैनोसेटेलाइट विकास पर हाल ही में शुरू किया गया था।

90.C

2- day first International Conference, on the theme- 'Sustainable Water Management', commenced at Indian School of Business (ISB), Mohali in Punjab. It was organized under National Hydrology Project, Union Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation by Bhakra Beas Management Board (BBMB). In the conference, Governor of Himachal Pradesh, Acharya Devvrat was the Chief Guest and Shri U.P. Singh, Secretary, Government of India, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation was the Guest of Honour. A CD of documentary entitled 'Bhakra Beas Nation's Pride' on BBMB was also released on the occasion. Countries like Australia, United Kingdom, USA, Spain, Netherlands, Republic of Korea, Canada, Germany, Sri Lanka etc. took part in the two-day conference.

2-दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 'सतत जल प्रबंधन' विषय पर, भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), पंजाब के मोहाली में शुरू हुआ था। यह राष्ट्रीय जलविद्युत परियोजना, जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, के तहत भाकडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि थे और भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के सचिव, श्री यूपी सिंह, सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर बीबीएमबी पर 'भाकडा ब्यास राष्ट्र की गौरव' नामक वृत्तचित्र की एक सीडी भी जारी की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्पेन, नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य, कनाडा, जर्मनी, श्रीलंका आदि जैसे देशों ने दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लिया।

91.C

Israel became a full member of the Financial Action Task Force (FATF), an international body set up to combat money laundering, terrorist financing and other threats to the international financial system. Earlier in 2000 the Jewish state was blacklisted by the organization and was removed from the list in 2002, but now has become the group's 38th member. A FATF compliance report on Israel ranked the country as one of three leading states, alongside the US and the UK, for the effectiveness of its anti-money laundering apparatus, its battle against terror financing, the work of its Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority, and its policy of seizing the financial proceeds of crime. The FATF membership will tag Israel as an attractive country for international investment and improve the status of the Israeli financial sector and its ability to operate in the global economy.

इज़राइल वित्तीय कार्य टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक पूर्ण सदस्य बन गया, जो एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो मनी लॉन्डरिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के अन्य खतरों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। इससे पहले 2000 में यहूदी राज्य को संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था और 2002 में सूची से हटा दिया गया था, लेकिन अब यह समूह का 38 वां सदस्य बन गया है। इजरायल पर एक एफएटीएफ अनुपालन रिपोर्ट ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ-साथ तीन प्रमुख राज्यों में से एक के रूप में देश को अपने एंटी-मनी लॉन्डरिंग तंत्र की प्रभावशीलता के लिए, आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई, इसके मनी लॉन्डरिंग और आतंक वित्त पोषण निषेध का कार्य प्राधिकरण, और अपराधी की वित्तीय आय को जब्त करने की इसकी नीति के लिए सदस्यता दी। एफएटीएफ सदस्यता अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए इज़राइल को एक आकर्षक देश के रूप में टैग प्रदान करेगी और इजरायली वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार करेगी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में काम करने की क्षमता में सुधार करेगी।

92.D

- The Global Risks Report 2019 has been released by the World Economic Forum (WEF).
- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा जारी किया गया है।

93.C

A Nishidhi stone inscription from the 12th century was found at Nandi Basaveshwara temple in Harakere village in Shivamogga district, Karnataka. The Nishidhi stone inscriptions are issued to commemorate Jain ascetics who perform Sallekhana vratha and inscription found here proves that there was a strong influence of Jainism in the region. The inscription is of 60 cm long and 15 cm wide and is chiselled from a schist rock slab.

12 वीं शताब्दी से एक निशिधि पत्थर शिलालेख कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के हरकेरे गांव में नंदी बसेश्वर मंदिर में पाया गया था। निशिधि पत्थर शिलालेख जैन तपस्या के लिए सलेखाना वृथा का प्रदर्शन करने वालों के लिए जारी किया जाता था और यहां पाए गए शिलालेख से साबित होता है कि इस क्षेत्र में जैन धर्म का एक मजबूत प्रभाव था। शिलालेख 60 सेमी लंबा और 15 सेमी चौड़ा है और एक शिष्ट रॉक स्लैब पर छेनी से काटा हुआ है।

94.B

the Uttar Pradesh Government announced creation of an umbrella university named after former Prime Minister late Atal Bihari Vajpayee. The decision was taken in a cabinet meeting headed by Chief Minister Yogi Adityanath at Lucknow. The University would be the controlling authority of all the medical and dental colleges and nursing institutions in the state. This would help in bringing transparency in entrance and examination system and would enhance quality of medical education.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अम्ब्रेला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मेंयह फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय राज्य में सभी चिकित्सा और दंत कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों का नियंत्रण प्राधिकरण होगा। इससे प्रवेश और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

95.D

a two day National conference 'AYUSHCHARYA' on Dinacharya (Daily Regimen) and Ritucharya (Seasonal Regimen) for public health promotion was organized by All India Institute of Ayurveda (AIIA) in New Delhi. Introducing a new term AYUSHCHARYA and citing scientific noesis of Dinacharya, Ratricharya and Ritucharya, Director AIIA Prof Tanuja Nesari gave the inaugural address to the conference. The conference was attended by nearly 200 academicians, physicians, scientists and researchers from all over country. The present conference was the part of celebration of 3rd National Ayurveda Day which was celebrated this year on November 5, 2018 on the occasion of the Dhanawantari Jayanti or Dhanteras with the theme "Ayurveda for Public health".

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान(एआईआईए) ने नई दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रचार के लिए दिनचर्या (दैनिक आहार) और ऋतुचर्या (मौसमी आहार) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'आयुषचर्या' आयोजित किया गया था। निदेशक एआईआईए प्रोफेसर तनुजा नेसरी ने एक नई परिभाषा "आयुषचर्या" का परिचय देते हुए और दिनचर्या (दैनिक आहार),रात्रिचर्या और ऋतुचर्या (मौसमी आहार) के वैज्ञानिक महत्व को बताते हुए सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में पूरे देश के लगभग 200 शिक्षाविदों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया था। वर्तमान सम्मेलन तीसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उत्सव का हिस्सा था, जिसे इस वर्ष 5 नवंबर, 2018 को धनवंतरी जयंती या धनतेरस के अवसर पर "सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद" विषय के साथ मनाया गया था।

96.D

Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Toxicology Research (CSIR-IITR), Lucknow has developed an innovative technology for "Drinking Water Disinfection System" with Trade name "OneerTM".

काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (CSIR-IITR), लखनऊ ने ट्रेड नाम "OneerTM" के साथ "पेयजल कीटाणुशोधन प्रणाली" के लिए एक नवीन तकनीक विकसित की है।

97.A

Saudi Journalist **Jamal Khashoggi** who was murdered at his country's Istanbul consulate in October was named **Time** Magazine's **"Person of the year"** along with a group of other persecuted journalists collectively called "the Guardians of the truth".

सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी जिनकी अक्टूबर में उनके देश के इस्तांबुल वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गयी थी, को टाइम मैगज़ीन के "पर्सन ऑफ़ द इयर" के साथ-साथ अन्य सताए गए पत्रकारों के एक समूह के साथ सामूहिक रूप से "सत्य के संरक्षक" कहा गया।

98.D

Petroleum Conservation Research Association (PCRA) is a registered society set up under the aegis of Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India.

- As a non-profit organization, PCRA is a national government agency engaged in promoting energy efficiency in various sectors of economy.
- PCRA aims at making oil conservation a national movement.
- Establish synergistic institutional linkages at the national & international levels in the areas of petroleum conservation & environment protection.

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है।

- एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में, पीसीआरए एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगी हुई है।
- पीसीआरए का उद्देश्य तेल संरक्षण को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है।
- पेट्रोलियम संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहक्रियात्मक संस्थागत संपर्क स्थापित करना।

99.D

An Israeli spacecraft on its maiden mission to the moon has sent its first selfie back to Earth. The image showing part of the Beresheet spacecraft with Earth in the background was beamed to mission control in Yehud, Israel – 37,600 kilometres (23,360 miles) away. चंद्रमा पर अपने पहले मिशन पर एक इजरायली अंतरिक्ष यान ने अपनी पहली सेल्फी पृथ्वी पर वापस भेज दी है। पृष्ठभूमि में पृथ्वी के साथ बेरेसैट अंतरिक्ष यान का हिस्सा दिखाती छवि को इज़राइल में मिशन नियंत्रण पर 37,600 किलोमीटर(23,360 मील) दूर प्रसारित गया।

100.A

Soumya Swaminathan who is currently a Deputy Director-General of the World Health Organisation (WHO) has been appointed as the Chief Scientist of the World Health Organisation (WHO). The Chief Scientist is a newly created position and division.This new division is the Department of Digital Health, in the Division of the Chief Scientist. She will oversee the digital work and help the department in assessing digital technologies, and help countries in deciding as to how to to prioritise, integrate and regulate them.

सौम्या स्वामीनाथन जो वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक उप महानिदेशक हैं, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। चीफ साइंटिस्ट एक नई बनाई गई स्थिति और डिवीजन है। यह नया डिवीजन डिजिटल हेल्थ का विभाग है जो चीफ साइंटिस्ट के सानिध्य में है। वह डिजिटल काम की देखरेख करेंगी और डिजिटल तकनीकों का आकलन करने में विभाग की मदद करेंगी, और देशों को यह तय करने में मदद करेंगी कि कैसे उन्हें प्राथमिकता, एकीकरण और विनियमन करना है।